Title: Need to provide financial assistance to Government of Bihar - Laid.

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : महोदय, किसी भी राज्य के आर्थिक वर्गीकरण का मानदंड होता है ''''जी.डी.पी.'''' अर्थात सकल घरेलू उत्पाद भुगतानों की बकाया राशि, मुद्रा की सुरक्षित निधि, आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में योजना विकास की स्थिति अन्य राज्यों से बदतर है। बिहार की वार्षिक योजना का आकार करीब 1300 करोड़ रूपये है। वर्ा 1998-99 में राज्यवार प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय 233 रूपये है जबकि असम और उड़ीसा में क्रमशः 500 और 679 रूपये रहा। 2000-2001 में ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार से जितने भी पैसे प्राप्त हुए उसमें से 434 करोड़ रू0 खर्च नहीं किये जा सके। पिछले दस वर्ाों में वृहद और मध्यम सिंचाई की एक भी योजना पूर्ण नहीं की जा सकी है। बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता 15 से 20 प्रतिशत रही है जबकि अन्य राज्यों का औसत 67 प्रतिशत है। बिहार राज्य वित्त आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गयी अन्तरिम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था विभाजन के बाद लड़खड़ा गयी है।

गत वर्ा 1999-2000 के बजट में 4894 करोड़ रू0 का वित्तीय घाटा दर्शाया गया है जबकि 98-99 में यह घाटा 4391 करोड़ था। सी.ए.जी. रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों से पता लगता है कि कुल व्यय का सामान्यतः 89 प्रतिशत राजस्व व्यय किया गया है जबकि अनुमानित पूंजीगत व्यय 5 प्रतिशत के मार्जिनल स्तर का रहा। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बिहार सरकार को आर्थिक संकट से उबारने हेतु समुचित सहयोग करें।